



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 84-2024/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 7, 2024 (JYAISTHA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 जून, 2024

संख्या 13/आ०-1/पं०अ०1/1914/धा० 58/2024.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल आवश्यक समझते हैं कि नियम तुरन्त लागू होने चाहिए; इसलिए, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 58 की उप-धारा (2) तथा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) संशोधन नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
(2) ये जून, 2024 के बारहवें दिन से लागू होंगे।
- हरियाणा रेस्तरां (मदिरा उपभोग) नियम, 1988 में, नियम 5 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इन नियमों के अन्य उपबंधों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नीति/आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन, शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित फीस संरचना पर प्ररुप अनु०-52 (शराब खाना) में अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सकती है:-

| क्रम संख्या | जिला के नाम | निर्धारित फीस (प्रति शराब खाना) |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | गुरुग्राम | जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 3 प्रतिशत |
| 2. | फरीदाबाद, पंचकुला तथा सोनीपत | जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 2 प्रतिशत |
| 3. | अन्य शेष जिले | जोन की अनुज्ञप्ति फीस का 1 प्रतिशत |

शराबखाना चारदिवारी के बिना खुले स्थान में संचालित नहीं किया जाएगा। शराबखाना एकांत में तथा बन्द होना चाहिए तथा सार्वजनिक मार्ग या चौराहा पर नहीं होगा, जिसका उपयोग जनसाधारण के लिए किया जा रहा है। भूतल पर शराबखाना का क्षेत्र छत से ढका होगा। साधारणतः शराबखाना राहगीरों के लिए दृश्यमान नहीं होगा तथा ऐसे स्थान में पहुंच उचित सीमांकित प्रवेश के द्वारा होनी चाहिए। सम्पूर्ण उद्देश्य, राहगीर के पूर्ण दृश्य में जनसाधारण को शराब पीने से रोकना है। शराबखाना निकटवर्ती कवर्ड स्थान में केवल एक निर्दिष्ट मंजिल से चलाया जाएगा। शराबखाना का क्षेत्र, शराबखाना के अनुमोदन के समय उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित क्षेत्र से बाहर अतिक्रमण नहीं करेगा। शराबखाना में किसी भी रीति में मदिरा बेची या परोसी नहीं जाएगी।

मदिरा उपभोग के लिए अधिकृत पीने के स्थानों को “शराबखाना” के रूप में जाना जाएगा। प्रति खुदरा जोन में केवल एक शराबखाना अनुज्ञात किया जाएगा। प्ररूप अनु0-52 में शराबखाना अनुज्ञप्ति शहरी क्षेत्रों और उप-शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निगम/परिषद्/समितियों की बाहरी सीमा और अन्य राज्यों के साथ सीमाओं से पांच किलोमीटर के भीतर आने वाले मदिरा के खुदरा ठेके केवल (अनु0-14क/अनु02) के साथ प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, महानगर विकास प्राधिकरण (जैसे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण इत्यादि) के अधीन आने वाले क्षेत्रों और ऐसे स्थान जहां हरियाणा राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट औद्योगिक पार्क जैसे औद्योगिक आदर्श नगरक्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगरक्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगरक्षेत्र, रोहतक, सूचना प्रौद्योगिक पार्क, मानेसर, सूचना प्रौद्योगिक पार्क पंचकूला इत्यादि विकसित किए हैं, में भी शराबखाना प्रदान किया जाएगा।

शराबखाना के लिए अनुज्ञप्ति संबंधित उप-आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी स्वयं शराबखाना चलाने का इरादा नहीं रखता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति को शराबखाना चलाने के लिए प्राधिकृत करेगा। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को पंजाब नशीली वस्तुओं के लाइसेंस और बिक्री आदेश, 1956 के अधीन प्रतिबंधित नहीं किया होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी उल्लंघन या आबकारी अधिनियम के उपबंधों/मानदंडों और नियमों और नीति के अधीन अधिरोपित शर्तों के भंग करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः जिम्मेदार होंगे।

अनुज्ञप्तिधारी से उचित ढांचा तथा फर्नीचर रखना तथा सफाई तथा स्वास्थ्यकर पर्यावरण बनाए रखने की अपेक्षा की जानी है। शराबखाना चलाने वाले अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत व्यक्ति के पास माल और सेवा कर और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पंजीकरण होना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक अग्निशमन उपकरण भी स्थापित करेगा और हरियाणा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (2022 का 14) यदि लागू हो, के मानदंडों की अनुपालन करेगा।”।

देविन्द्र सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 7th June, 2024

No. 13/X-I/P.A.1/1914/S. 58/2024.— Whereas the Governor of Haryana considers necessary that the rules should be brought into force at once; so in exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-sections (2) and (3) of section 58 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Amendment Rules, 2024.
- (2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2024.
2. In the Haryana Restaurant (Consumption of Liquor) Rules, 1988, in rule 5, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Subject to other provisions of these rules and policy/orders/instructions issued by the competent authority, a license in form L-52 (Tavern) may be granted in urban areas on the following fee structure:-

| District | Fixed fee per Tavern |
|----------------------------------|---------------------------|
| Gurugram | 3% of license fee of zone |
| Faridabad, Panchkula and Sonapat | 2% of license fee of zone |
| Other remaining districts | 1% of license fee of zone |

The Tavern shall not be operated in an open space without boundary. The space shall be confined to and enclosed and shall not be a thorough fare or a crossing being used by general public. The area of tavern at ground floor shall be covered with roof. The space shall not be ordinarily visible to the passersby and the access to such a space should be through a well defined entry. The overall objective is to prevent drinking in public in full view of the passersby. Tavern can be operated from only one designated floor in adjoining covered space. The area of Tavern shall be approved by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) at the time of approval of the Tavern and licensee shall not encroach beyond the area approved. Liquor shall not be sold or served in any manner in the Tavern.

The authorized drinking places for consumption of liquor shall be known as “Taverns”. Only one Tavern per retail zone shall be allowed. The tavern license in form L-52 shall be granted with the retail vends of liquor (L-14A/L-2) only in urban areas and sub-urban areas falling within 5 KMs from the outer limit of respective Municipal Corporation/ Council/ Committees and borders with other States. In addition, Tavern shall also be granted in the areas under Metropolitan Development Authorities (like Gurugram Metropolitan Development Authority, Panchkula Metropolitan Development Authority etc.), and places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and theme/specialized industrial parks like Industrial Model Townships Manesar, Industrial Model Townships Bawal, Industrial Model Townships Rohtak, Information Technology Park Manesar, Information Technology Park Panchkula, etc.

The license for tavern shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned. In case the retail licensee does not intend to run tavern by himself/herself, the licensee with the approval of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned, authorize any other person for running tavern. Such authorized person should not have been barred under the Punjab Intoxicant License and Sales Order, 1956. The licensee as well as authorized person shall be jointly and severally responsible for any violation or breach of provisions/norms of the Excise Act and rules and the conditions imposed under the Policy.

The licensee is required to have proper structure and furniture and to maintain cleanliness and hygienic environment. The licensee or his authorized person running Tavern shall have GST and FSSAI registration. The licensee shall install necessary fire-fighting equipment and comply with the norms of the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022 (14 of 2022), if applicable, in the approved premises of Tavern”.

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.